INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 5.71 (SJIF 2021)

भारत की नई आर्थिक नीति का रोजगार पर प्रभाव
(Impact of India's New Economic Policy on Employment)

डॉ. प्रवेश कुमार (पाण्डेय)
असिस्टेण्ट प्रोफेसर
जवाहर लाल नेहरू डिग्री कॉलेज,
एटा (उत्तरप्रदेश)
E-mail: praveshkumarpandey1971@gmail.com

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/01.2022-66141124/IRJHIS2201010

प्रस्तावना :

किसी देश के आर्थिक विकास में आर्थिक नीति की भूमिका उसकी उद्देश्यों में निहित होती है। एक उपयुक्त नीति को अपनाकर ही कोई देश सम्मान तथा न्याय के साथ सन्तुलित आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक नीति किसी देश के विदेशी व्यापार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करने के साथ–साथ विदेशों के साथ राजनैतिक सम्बन्धों को भी प्रभावित करती है। किसी देश का विदेशों से सकारात्मक सम्बन्ध उसके विकास को गतिशील बनाने में सहायक होते हैं। हम कह सकते हैं कि आर्थिक नीति से अभिप्राय कतिपय विशिष्ट आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनायी जाने वाली विधि से है। अतः आर्थिक नीति के अन्तर्गत देश की आकांक्षा के अनुरूप कतिपय लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं तथा देश में उपलब्ध आवश्यक संसाधनों को समुचित विदोहन कर उन लक्ष्यों की प्राप्त का प्रयास किया जाता है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक नीति का निर्माण किया जाता है और आर्थिक निर्माण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को हम एक चार्ट द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं।

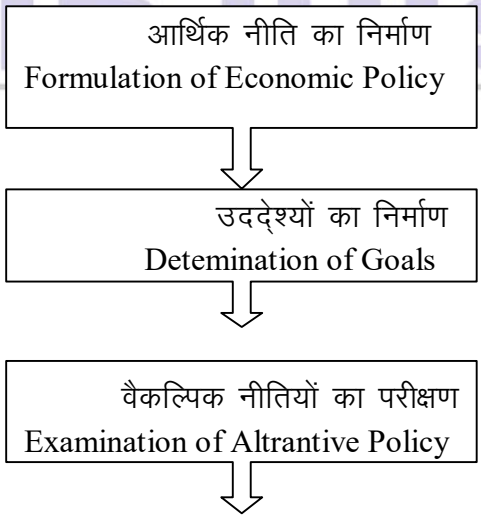

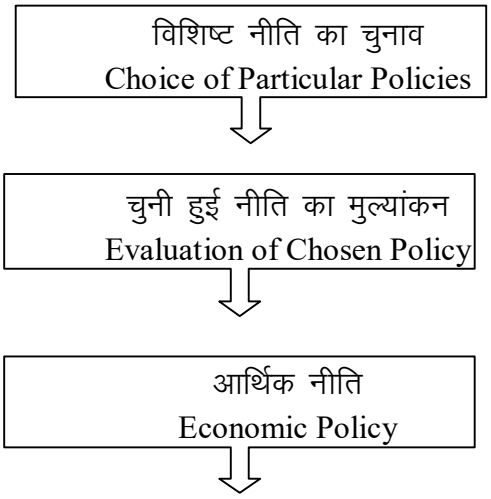

अतः हम संक्षेप में कह सकते हैं कि ''आर्थिक नीति सरकार की उन क्रियाओं को कहते हैं जो सरकार आर्थिक क्षेत्र में लेती है''[1] सरकार द्वारा जुलाई 1991 के बाद से देश को आर्थिक संकट से निकालने तथा विकास की गति को तीव्र करने के जो विभिन्न नीतिगत आर्थिक सुधारों की श्रृंखला अपनायी गयी सामान्य रूप से उसे हम भारत की नई आर्थिक नीति का नाम दे सकते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति से अभिप्राय जुलाई 1991 के बाद से किये गये विभिन्न नीतिगत उपायों और परिवर्तनों से है जिनका उद्देश्य अर्थ व्यवस्था को उदारीकरण की परिधि में लाकर उसे प्रतियोगी बनाकर उत्पादकता और कुशलता में वृद्धि करना है क्योंकि नई आर्थिक नीति के उद्देश्य भी इस प्रकार हैं।

1. अतीत में प्राप्त लाभों का समायोजन करना।
2. अर्थ व्यवस्था में विकास की दर को बढाना।
3. उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता एवं उत्पादका स्थल में सुधार लाना।
4. उत्पादन इकाइयों की प्रतिस्पर्द्धत्मक क्षमता को बढाना।
5. आर्थिक विकास के वास्ते विश्व व्यापी संसाधनों का प्रयोग करना आदि।

नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंगों में :

1. नई औद्योगिक नीति।
2. नई व्यापार नीति।
3. नई राजकोषीय नीति।
4. नई मौद्रिक नीति।
5. नई निवेश नीति प्रमुख रूप से है।

नई आर्थिक नीति के अवयवों में प्रथम उदारीकरण दूसरा निजीकरण तीसरा वैश्वीकरण प्रमुख है– 1991 के दशक के प्रारम्भ में नरसिंहराव की सरकार के आगमन के साथ ही नई आर्थिक नीति में औद्योगिक, व्यापारिक, वित्तीय मौद्रिक इत्यादि क्षेत्रों में आर्थिक नीति के अवयवों का प्रचार किया गया। निजीकरण को बढावा दिया गया सार्वजनिक क्षेत्र को संकुचित करके सुरक्षित उद्योगों की संख्या 18 थी। जिसे नई नीति में 3 कर दिया गया निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित किया गया औद्योगिक लाइसेसिंग की अनिवार्यता समाप्त करते हुए वर्तमान में केवल 5 उद्योगों को लाइसेसिंग अनिवार्यता में रखा गया सार्वजनिक क्षेत्रों की बिक्री आरम्भ

की गई अतः नई आर्थिक नीति में अपनाये हुए सुधारवादी उपायों की परिणति आज उदारीकरण और निजीकरण की सीमा से निकलकर अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण के रूप से परिलक्षित हो रही हैं। विश्व व्यापीकरण को सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि ''विश्व व्यापीकरण वह प्रकिया है जिसमें बाजारों के मध्य पारस्परिकनिर्भरता उत्पन्न होती है और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबन्धित न रहकर विश्व व्यापार में निहित तुल्नात्मक लागत दशाओं को विदोहन करने की दिशा में होता है'' संक्षेप में विश्वव्यापीकरण राष्ट्रों की राजनैतिक सीमाओं के आरपार आर्थिक लेन–देन की प्रक्रियाओं और उनके प्रबन्धन का प्रवाह है।''

नई आर्थिक नीति की उपलब्धियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पायेंगे कि हमने देश की राष्ट्रीय आय में, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, कीमत स्तर, विदेशी व्यापार, विदेशी मुद्रा विनिमय कोष, विदेश प्रत्यक्ष निवेश, राजकोषीय घाटा आदि में अत्यधिक सफलता अर्जित नहीं कर पाई है। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में वृद्धि का आंकड़ा बढा है परन्तु फिर भी हमें इसे और अधिक सफल बनाने की जरूरत है।

नई आर्थिक नीति का बुनियादी इरादा भारतीय अर्थव्यवस्था के अवयवों को मजबूती के साथ आर्थिक विकास के रास्ते को आगे बढाना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने नियंत्रणात्मक ढांचे की समाप्ति के लिये पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लिये औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली की अनिवार्यताओं को समाप्त कर दिया गया है। उत्पादकता में गुणात्मक विकास के लिये विदेशी तकनीक के आयात प्रतिबन्धों को उदार एवं मुक्त बनाया गया है। इस प्रकार बहुआयामी औद्योगिक नीति सुधारों द्वारा भारतीय उद्योग में संरक्षणवाद को समाप्त किया गया है और प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण बनाया गया है।

डॉ राजा चैल्लैया की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 1993 – 1994 के बजट प्रस्तावों में सीमा शुल्कों और उत्पाद शुल्कों में व्यापक कटौती की थी। इसका परिणाम यह हुआ है कि तब से लेकर वर्तमान समय तक विदेशी मशीनरी और तकनीक के आयातों का कार्य अधिक सरल बनाकर उदारीकरण एवं विश्व व्यापीकरण के अभियान को और ज्यादा असरदार बनाने का प्रयास किया गया है। इन सबका परिणाम यह हुआ है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में नई आर्थिक नीति का प्रभाव रोजगार पर पढा है। क्योंकि सरकारद्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना दिसम्बर 1997 में प्रारंभ की गई इसका प्रमुख उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। (SJSRY) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को खेप सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना।

प्रधानमत्री ग्रामीण सडके योजना 25 दिसम्बर 2000 को प्रारंभ की गई इसका उद्देश्य 500 तक आवादी वाले सभी गांवों को सड़क से जोड़ना।

जयप्रकाश गारंटी योजनाः– यह योजना फरवरी 2001 में लागू की गई इसका उद्देश्य देश के सर्वाधिक जनपदों में बेरोजगारी को सुनिश्चित करना और अन्हे रोजगार देना। काम के बदले अनाजः–नवम्बर 2004 में लागू की गयी इसका उद्देश्य प्रत्येक कार्य दिवस के लिए 5कि0ग्रा0 अनाज प्रतिदिन दिया जाना सुनिश्चित किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना– 2 फरवरी 2006 में लागू की गई जिसका उद्देश्य रोजगार के इच्छुक

एवं पात्र व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण कराने के 15 दिन के भीतर रोजगार न दिये जाने पर न्यूनतम मजदूरी 1/3 दर से बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा दिया जायेगा। मैला ढोने वाले व्यक्तियों के लिये दिसम्बर 2006 में योजना लागू की गयी इसके माध्यम से इन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था।

स्किल डेवलपमेंट योजनाः– दिसम्बर 2006 में लागू की गयी। इस योजना में कम पढ़े–लिखे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 15 अगस्त 2008 को लागू की गयी। इसका उद्देश्य स्वरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान कराना था।

अतः हम कह सकते है कि सरकार ने वर्तमान योजना काल में भी अनेक रोजगार से सम्बन्धित योजनायें चलाई हैं। परन्तु वह ज्यादा कारगर सावित नही हो रही हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में सरकार द्वारा सेवा योजन कार्यालयों जो भारत के प्रत्येक जनपद में स्थित हैं रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। नव युवकों को रोजगार मिल रहा है परन्तु इसका प्रभाव रोजगार पर बहुत ही न्यून है। हमने नई आर्थिक नीति का विश्लेषण सही तरीके से नहीं कर पाया है जिसका परिणाम रोजगार पर पड़ा है। हमने विकसित राष्ट्रों की नकल में अक्ल से काम नहीं लिया। बिना श्रम शक्ति के बाहुल्य को ध्यान में रखते हुये हमने श्रमवचत विधियों की पहल की।

परिवार नियोजन कार्यौक्रमों में विलम्ब हुआ है। मानव शक्ति में नियोजन का अभाव रहा क्योंकि योजना आयोग द्वारानियुक्त विशेषज्ञ समिति पहले ही कह चुकी थी। '' इस देश की पेचीदा अर्थ व्यवस्था में श्रम शक्ति, रोजगार, और बेरोजगारी की प्रकृति इतनी भिन्न है कि सभी बेरोजगारों को एक ही श्रेणी में रखकर देखना ठीक नहीं है''[2]

रोजगार की ऊंची सवृद्धि दर प्राप्त करने के लिये उत्पादन से वृद्धि आवश्यक तो है। परन्तु सदैव ही इसे समुचित दिशा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है जो क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में श्रम रोजगार उपलब्ध कराते हुए राष्ट्रीय आय में भी अच्छा योगदान देते हैं उनसे रोजगार सृजन की अच्छी दशा सदैव रहती है दक्षता और उत्पादकता के स्तर को गिराये बिना तथा प्रतिस्पर्द्धात्मकता को कम किये बिना अधिकांश उत्पादन गतिविधियों के मामले में विभिन्न प्रकार की तकनीकों का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। हम यहां यह भी स्वीकार करते हैं कि अर्थ व्यवस्था के एक बढे क्षेत्र में कृषि तथा असंगठित विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में तकनीक की उन्नयन उत्पादकता स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। उत्पादन के सभी क्षेत्रों में संगठित एवं असंगठित में उत्पादकता के उन्नयन द्वारा रोजगार अवसरों में वृद्धि की जा सकती है। रोजगार में वृद्धि मुख्य रूप से अर्थ व्यवस्था के विकास एवं समृद्धि के घटकों की पुर्न संरचना के परिणाम स्वरूप होनी चाहिए। इसमें संदेह नहीं है कि श्रम के अधिकाधिक प्रयोग से समृद्धि दर में तेजी से वृद्धि होगी। लेकिन यह तभी संभव हो सकेगा जब श्रम को पूंजी तथा आंतरिक एवं वाहृय मांग का सहयोग प्राप्त होगा। रोजगार, सम्भाव्यता को ऐसे क्षेत्र व उपक्षेत्र में उत्पादन की संरचना की पुनः संयोजन द्वारा भी बढाया जा सकता है। सरकार द्वारा नियोजन के माध्यम से पंचवर्षी योजनाओं के द्वारा लगातार रोजगार बढाने के प्रयास किये गये हैं। परन्तु पंचवर्षीय योजनाऐं पूर्ण रोजगार का उद्देश्य प्राप्त करने में सर्वथा असमर्थ रही हैं। रोजगार की स्थिति ठीक न होने के कारण भारत में अनेक समस्याओं का जन्म हुआ है जैसेः– मानव शक्ति का व्यर्थ जाना, सामाजिक समस्याओं को जन्म देना, राजनैतिक अस्थिरता आर्थिक सम्पन्नता में कमी अन्य दुष्परिणाम आदि। बेरोजगारी से सामाजिक,

राजनैतिक और आर्थिक वातारण दूषित हो जाता है। इसलिए विलियम वेबरिज ने लिखा है ''बेरोजगार रखने के स्थान पर लोगों को गढ्ढे खुदवाकर वापस भरने के लिये नियुक्त करना ज्यादा अच्छा है''हम निश्चित रूप से आंकलन कर सकते हैं कि नई आर्थिक नीति निर्धनता उन्मूलन केसम्बन्ध में पूर्णतः असफल रही है। इसका मुख्य कारण यह है किः–

1. निर्धन वर्ग के लाभ की योजनाओं पर किये जाने वाले सार्वजनिक व्ययों पर कमी की गयी है।
2. भोजन तथा कृषि पदार्थों पर दिये जाने वाली वास्तविक सब्सिडी को कम किया गया है।
3. सरकारी धन का नितान्त दुरूपयोग किया गया है।
4. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक योजनाऐं बनायी गयी परन्तु वह केवल कागजी ही रहीं वास्तविक धरातल पर वह कार्य दिखायी नहीं दे रहे हैं।
5. योजनाबद्ध तरह से भ्रष्टाचार को बढावा दिया गया है जिसका परिणाम बेरोजगारी का विशालतम रूप देखने को मिल रहा है। हमारे देश के पासअभी उतने संसाधन प्रतिस्पर्द्धात्मक नहीं हैं। जितने विकसित देशों के हैं उनके सामने हमें नई आर्थिक नीति के माध्यम से खड़ा कर दिया गया और परिणाम यह हुआ है कि हम उनके सामने असफल हुए। नई आर्थिक नीति के माध्यम से सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिये 1991 के बाद से निरन्तर प्रयास किये गये हैं। जैसे विनियोग दर में वृद्धि की गयी हैं। गांवों को सड़कों एवे बिजलीघरों से जोड़ा गया है। जनशक्ति नियोजन का प्रयोग किया गया है। कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास किया गया है, कृषि तकनीकों में अत्यधिक उन्नतिशील तनीक प्रयोग की गई है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग में नई तकनीक प्रयोग की गई है। कुटीर एवं लघुउद्योगों का विकास किया गया है। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया गया है। जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण लगाने के लिये सरकार ने सराहनीय प्रयास किये हैं, राष्ट्रीय श्रम आयोग बनाया गया है, कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की गयी है। प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक रोजगार दफ्तर बनाने का प्रयास किया गया है। परन्तु नई आर्थिक नीति का परिणाम अभी ज्यादा कारगार साबित होता नहीं दिखायी दे रहा है। अनेक सरकारी प्रयास जैसे सामान्य रोजगार को बढाना, नियोजन सेवाऐं बेरोजगारी भत्ता, महात्मा गांधी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (मनरेगा) आदि का संचालन किया गया है। अनेक कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा रोजगार को बढाने के लिये चलाये जा रहे हैं। परन्तु अभी भी हमारे देश में वेरोजगारी की समस्या एक बहुत बढी समस्या के रूप में खड़ी है। जहां नई आर्थिक नीति ने हमारे कौशल को बढाने का कार्य ज्यादा नहीं किया है। अपितु हमें असमंजस की स्थिति में डाला है। नई आर्थिक नीति के कारण हालांकि हमने अपने आर्थिक ढांचे में सुधार किया गया है। सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं शैक्षिक विकास भी हुआ है परन्तु इस नई आर्थिक नीति ने हमारे सार्वजनिक क्षेत्र को लगातार कम करने की कोशिश की है। निजी क्षेत्र को बढावा देने के बावजूद तकनीकी कार्य ने रोजगार को बढाने का कार्य नहीं किया बल्कि एक तरह से लोगों में मानसिक अवसाद पैदा कर दिया है। निरन्तर विकसित देशों की प्रतिस्पर्द्धात्मक कार्य प्रणाली के कारण हम अच्छे बाजारों में सही तरह से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। निरन्तर घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को सरकार ने उन्हें बन्द करने के प्रयास किये हैं। जिसका परिणाम रोजगार पर प्रभाव बुरा पढा है

अतः हम कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति के कारण बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। नई आर्थिक नीति ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के निवेश को बहुत महत्व दिया गया परन्तु यह कम्पनियां पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करती हैं। जिसके कारण रोजगार सृजन नहीं हो पाता है। फलतः वर्तमान में बेरोजगारी की दर निरन्तर बढ रही है। नई आर्थिक नीति ने हमें अनेक नये आयाम दिये हैं। परन्तु रोजगार पर इसका प्रभाव अभी ज्यादा सफल दिखाई नहीं दे रहा है। नई आर्थिक नीति ने कई क्षेत्रों में रोजगार को बढाने का प्रयास भी किया है परन्तु वर्तमान में इसके प्रभाव रोजगार की दृष्टि से ज्यादा सफल नहीं हुए हैं।

अतः सरकार को नई आर्थिक नीति में उन बिन्दुओं को अनिवार्य रूप से सम्मलित करने की जरूरत है। जिनसे रोजगार पर अच्छा प्रभाव पढे और रोजगार बढे।

सन्दर्भ सूची :

1. क्रिस्टल तथा लिपसी– भारत की नई आर्थिक नीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स संस्करण 2021–22 पृष्ठ– 6
2. प्रोफेसर ओझा बी एल, भारत की आर्थिक समस्याऐं, साहित्य भवन पब्लीकेशन्स संस्करण 2012 पृष्ठ 142,
3. भारतीय अर्थ व्यवस्था..... राघवेन्द्र सिंह।
4. अर्थशास्त्र, उ प्र लोक सेवा आयोग..... डॉ अग्रवाल अनुपम।
5. डॉ सिन्हा बी सी, भारतीय आर्थिक समस्याऐं, एस बी पी डी पब्लिकेशन्स हाउस आगरा संस्करण 2015
6. डॉ सिन्हा पुष्पा, भारतीय आर्थिक समस्याऐं, एस बी पी डी पब्लिकेशन्स हाउस आगरा संस्करण 2015